

प्रेषक,

डॉ० उमाकांत पंवार,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,

सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग:-1

देहरादून, दिनांक 27 जनवरी, 2014

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 की प्रथम अनुपूरक अनुदान की मांगों में पैक्स मिनी बैंकों में जमा निक्षेपों हेतु निक्षेप गारन्टी योजना (कॉरपस फण्ड) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या-3593/नियो0/कॉरपस फण्ड/2013-14 दिनांक 24 सितम्बर, 2013 तथा वित्त विभाग के आदेश संख्या:-284/XXVII (1)/2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 व अनुपूरक अनुदान की मांगों की स्वीकृति सम्बन्धी आदेश संख्या:-668/XXVII (1)/2013 दिनांक 08 अक्टूबर, 2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 की प्रथम अनुपूरक अनुदान की मांगों में पैक्स मिनी बैंकों में जमा निक्षेपों के लिये निक्षेप गारन्टी योजना (कॉरपस फण्ड) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रुपये 6,38,000/- (छः लाख अड़तीस हजार मात्र) को निम्नांकित शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त योजना सम्बन्धी शासनादेश संख्या:-6938-43/व0ग्रा0वि0/सह0/2003-04 दिनांक 17 मार्च 2004 के निर्देशों के अनुसार प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में जमा निक्षेपों के लिये निक्षेप गारन्टी योजना नियमावली, 2004 की शर्तों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार का अंशदान विगत वित्तीय वर्ष में दिनांक 31 मार्च तक जमा निक्षेप का वार्षिक अंशदान 0.30 प्रतिशत की दर से (वर्ष दौरान निक्षेप राशि पर वृद्धि) अनुमन्य होगा।

(3) प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति, जिला सहकारी बैंक एवं शीर्ष बैंक के अंशदान जो कि क्रमशः 0.15, 0.10 एवं 0.05 (वर्ष के दौरान वृद्धि निक्षेप राशि पर) है, जमा किया जाय। उक्त योजना का अनुश्रवण दी गयी व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित किया जाय तथा उसकी प्रगति से शासन को भी अवगत कराया जाय।

(4) उक्त धनराशि ऐसे किसी मद/कार्य पर व्यय न की जाय जो योजना में स्वीकृत नहीं है, यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अलग मद में किया जाता है, तो सम्बन्धित अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(5) उक्त धनराशि का व्यय विवरण प्रत्येक माह के अन्त में या अगले माह की 5 तारीख तक बी0एम0-8 पर नियमित रूप से वित्त विभाग एवं शासन तथा महालेखाकार उत्तराखण्ड को भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए।

(6) उक्त व्यय शासन के वर्तमान नियमों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय की उक्त धनराशि को किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित हो। प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी जारी आदेशों का व वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।



(2)

- 2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-18 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक 2425-सहकारिता-आयोजनेत्तर-00-800-अन्य व्यय-10-पैक्स मिनी बैंको में जमा निक्षेपों के लिये निक्षेप गारन्टी योजना-00-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।
- 3- ये आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-86(P)/XXVII-4/2013, दिनांक 13 जनवरी, 2014 द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।
- संलग्नक-आई0डी0 मूल में।

भवदीय,

(डॉ० उमाकांत पंवार)  
सचिव।

संख्या-(674(1)/XIV-1/2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा निबन्धक।
4. वित्त अनुभाग-4/नियोजन विभाग/भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
6. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
7. प्रभारी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
8. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(यू0सी0 कबडवाल)  
अपर सचिव।